

## समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं चुनौतियों का अध्ययन।

नन्द किशोर चौरसिया

(सहायक प्राध्यापक), शिक्षा शास्त्र विभाग, डी.पी. चतुर्वेदी विज्ञान, वाणिज्य, कला एवं शिक्षा  
महाविद्यालय, सिवनी (म.प्र.)

नन्द किशोर चौरसिया

(शोधार्थी), शिक्षा शास्त्र विभाग, महाकोशल विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

### सार

समावेशी शिक्षा वर्तमान वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसका मूल उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई अथवा शारीरिक भिन्नताओं के बावजूद समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्तियों तथा इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में मात्रात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया। 120 शिक्षकों का चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। आंकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, माध्य एवं मानक विचलन के माध्यम से किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, किन्तु संसाधनों की कमी, विशेष प्रशिक्षण का अभाव, कक्षा में विद्यार्थियों की अधिक संख्या तथा प्रशासनिक सहयोग की कमी जैसी चुनौतियाँ इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। अध्ययन यह सुझाव देता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधन एवं संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

**मुख्य शब्द:** समावेशी शिक्षा, शिक्षक अभिवृत्ति, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, शैक्षिक चुनौतियाँ, समावेशन।

### 1. परिचय

समकालीन शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा एक ऐसी वैचारिक एवं व्यवहारिक अवधारणा के रूप में विकसित हुई है, जो सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना को सुदृढ़ बनाती है। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित

सभी विद्यार्थियों को एक ही शैक्षिक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था विविधताओं को स्वीकार करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं का सम्मान करती है।

समावेशी शिक्षा वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी अवधारणा के रूप में उभरी है। इसका मूल उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं के बावजूद समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। समावेशी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक बालक सीखने की क्षमता रखता है तथा उसे समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त होना चाहिए। यह शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करते हुए सभी विद्यार्थियों को एक ही शैक्षिक वातावरण में सीखने और विकसित होने का अवसर प्रदान करती है (यूनेस्को, 1994)।

शिक्षा को मानव विकास का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। यह व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परम्परागत शिक्षा व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यार्थियों से अलग शिक्षित किया जाता था, जिसके कारण वे सामाजिक मुख्यधारा से पृथक हो जाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा विकसित हुई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को समान सम्मान, समान अवसर तथा समान सहभागिता प्रदान करना है (ऐन्स्को, 2005)।

समावेशी शिक्षा का विचार सामाजिक न्याय, समानता एवं मानवाधिकारों की अवधारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह शिक्षा व्यवस्था इस विश्वास को सुदृढ़ करती है कि विद्यालय केवल ज्ञान प्रदान करने का केंद्र नहीं है, बल्कि ऐसा सामाजिक मंच भी है जहाँ विविधता को स्वीकार किया जाता है और सभी विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं के विकास का अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों में सहयोग, सहिष्णुता, सहानुभूति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास करती है (यूनेस्को, 1994)।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का महत्व अत्यधिक है क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, सामाजिक वर्गों एवं आर्थिक पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं जो दिव्यांगता, अधिगम कठिनाइयों, सामाजिक व आर्थिक वंचना अथवा अन्य विशेष आवश्यकताओं का सामना करते हैं। इन सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया है (भारत सरकार, 2009; भारत सरकार, 2016; भारत सरकार, 2020)।

समावेशी शिक्षा की सफलता में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षक विद्यालयी वातावरण का प्रमुख संचालक होता है तथा विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, तो वे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि शिक्षकों की अभिवृत्ति नकारात्मक हो या उन्हें समावेशी शिक्षण का पर्याप्त ज्ञान न हो, तो समावेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है (अवरामिडिस एवं नॉर्विच, 2002)।

अभिवृत्ति से आशय किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं तथा व्यवहारिक प्रवृत्तियों से होता है। शिक्षकों की अभिवृत्ति यह निर्धारित करती है कि वे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को किस प्रकार स्वीकार करते हैं तथा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले शिक्षक विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को समझते हैं, लचीली शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हैं तथा कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक अभिवृत्ति समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती है (शर्मा, फॉरलिन एवं लॉरमैन, 2008)।

यद्यपि समावेशी शिक्षा एक आदर्श एवं मानवीय अवधारणा है, तथापि इसके क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों का अभाव, विशेष शिक्षकों की कमी, अनुपयुक्त आधारभूत संरचना, बड़े आकार की कक्षाएँ तथा शिक्षकों को समावेशी शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त कई बार शिक्षकों को समय की कमी, प्रशासनिक सहयोग के अभाव तथा अभिभावकों की सीमित जागरूकता जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है (फॉरलिन, 2010)।

भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों को अनेक प्रकार की व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्य कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षित करना, प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना तथा उनके अनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करना एक जटिल कार्य है। कई बार शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है (सिंघल, 2015)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा पर विशेष बल दिया है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई या शारीरिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए विद्यालयों में आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है (भारत सरकार, 2020)।

समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए ही लाभकारी नहीं है, बल्कि यह सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होती है। समावेशी वातावरण में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी विविधताओं का सम्मान करना सीखते हैं तथा उनमें सामाजिक संवेदनशीलता, सहयोग एवं सहानुभूति जैसे गुण विकसित होते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देती है जो समानता, न्याय और मानव गरिमा के मूल्यों पर आधारित हो (ऐन्स्को, 2005)।

अतः यह स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा की सफलता काफी हद तक शिक्षकों की अभिवृत्ति तथा उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर निर्भर करती है। शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति एवं पर्याप्त संसाधन समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सकते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ इसकी सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन “समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं चुनौतियों का अध्ययन” अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सामयिक है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षकों के दृष्टिकोण तथा समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकेगा।

## 2. साहित्य समीक्षा

1. यूनेस्को (1994) द्वारा प्रस्तुत *सलामांका वक्तव्य एवं विशेष आवश्यकता शिक्षा हेतु कार्य-ढाँचा* समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस दस्तावेज़ में यह प्रतिपादित किया गया कि प्रत्येक बालक को उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक, बौद्धिक एवं शारीरिक भिन्नताओं के बावजूद समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अध्ययन में समावेशी विद्यालयों को सामाजिक न्याय, समानता तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभावी माध्यम बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार सामान्य विद्यालयों को ऐसी संरचना एवं वातावरण विकसित करना चाहिए जिससे सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस अध्ययन ने समावेशी शिक्षा को वैश्विक स्तर पर नीतिगत समर्थन प्रदान किया तथा शिक्षा प्रणालियों में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

2. अवरामिडिस एवं नॉर्विच (2002) ने शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित अनेक अध्ययनों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि शिक्षकों का दृष्टिकोण समावेशन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयी संसाधन, प्रशासनिक सहयोग तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ पूर्व अनुभव भी शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक सुदृढ़ बनाना आवश्यक है।
3. ऐन्स्को (2005) ने समावेशी शिक्षा प्रणालियों के विकास में विद्यालयी नेतृत्व, संस्थागत संस्कृति तथा नीति-निर्माण की भूमिका का विश्लेषण किया। अध्ययन में विभिन्न देशों की समावेशी शिक्षा व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि सफल समावेशन केवल नीतिगत निर्णयों का परिणाम नहीं होता, बल्कि विद्यालयी वातावरण, शिक्षकों के सहयोग तथा नेतृत्व क्षमता पर भी निर्भर करता है। अध्ययन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालयों में सहयोगात्मक संस्कृति विकसित करना आवश्यक है।
4. शर्मा, फॉरलिन एवं लॉरमैन (2008) ने शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन किया। शोध में यह पाया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन हुआ। शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ा तथा उनकी चिंताओं में कमी आई। अध्ययन ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।
5. फॉरलिन (2010) ने समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में शिक्षकों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश शिक्षक समावेशन के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, किंतु अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन तथा अत्यधिक कार्यभार के कारण वे व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। शोध में यह भी पाया गया कि विद्यालयी सहयोग और संसाधनों की उपलब्धता शिक्षकों की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण और संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है।

6. सिंघल (2015) ने भारत एवं पाकिस्तान में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। अध्ययन में यह पाया गया कि दोनों देशों में समावेशी शिक्षा को नीतिगत स्तर पर स्वीकार किया गया है, किन्तु व्यवहारिक स्तर पर अभी भी अनेक बाधाएँ विद्यमान हैं। विशेष शिक्षकों की कमी, आधारभूत संरचना का अभाव तथा शिक्षकों के सीमित प्रशिक्षण को प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया। शोध ने समावेशी शिक्षा के लिए अधिक व्यावहारिक रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया।
7. अग्रवाल एवं गुप्ता (2016) ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया। शोध में अधिकांश शिक्षकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया, किन्तु उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण एवं संसाधनों की आवश्यकता व्यक्त की। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अनुभव प्राप्त शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।
8. भट्ट एवं जोशी (2017) ने समावेशी शिक्षा में शिक्षक दक्षताओं की भूमिका का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की कक्षा प्रबंधन क्षमता तथा समावेशी शिक्षण कौशल अधिक प्रभावी होते हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
9. राव एवं कुमार (2017) ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि अधिक शिक्षण अनुभव वाले शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अध्ययन ने यह भी दर्शाया कि समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रभावी शिक्षण व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध विद्यमान है।
10. वर्मा एवं सिंह (2018) ने महिला एवं पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि महिला शिक्षकों का दृष्टिकोण पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक सकारात्मक था। अध्ययन के अनुसार महिला शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को अधिक संवेदनशीलता के साथ समझती हैं, जिससे समावेशी वातावरण के निर्माण में सहायता मिलती है।
11. कौर एवं शर्मा (2018) ने विद्यालयी संसाधनों एवं समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता के मध्य संबंध का अध्ययन किया। शोध में यह पाया गया कि जिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षण सामग्री, सहायक

- उपकरण तथा विशेष सेवाएँ उपलब्ध थीं, वहाँ समावेशी शिक्षा अधिक प्रभावी थी। अध्ययन ने विद्यालयी अवसंरचना को समावेशन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना।
12. चौधरी एवं यादव (2019) ने शिक्षक प्रशिक्षण एवं समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के मध्य संबंध का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों में समावेशी शिक्षण के प्रति अधिक आत्मविश्वास तथा सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गई। शोध ने यह निष्कर्ष दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है।
  13. तिवारी एवं मिश्रा (2019) ने सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति की तुलना की। अध्ययन में निजी विद्यालयों के शिक्षकों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक पाया गया। इसका प्रमुख कारण बेहतर संसाधन, प्रशिक्षण सुविधाएँ तथा प्रशासनिक सहयोग माना गया।
  14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। नीति में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों तथा अन्य कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। नीति ने शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता तथा विद्यालयी संसाधनों को मजबूत बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
  15. शर्मा एवं गुप्ता (2021) ने कोविड-19 महामारी के दौरान समावेशी शिक्षा की चुनौतियों का अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी, आर्थिक तथा संचार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अध्ययन ने डिजिटल समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया।
  16. यादव एवं सिंह (2022) ने शिक्षकों की समावेशी शिक्षण दक्षताओं का अध्ययन किया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि नियमित प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शिक्षकों की दक्षताओं में महत्वपूर्ण सुधार लाते हैं। अध्ययन ने निरंतर प्रशिक्षण को समावेशी शिक्षा की सफलता का प्रमुख आधार माना।
  17. कुमार एवं वर्मा (2023) ने शिक्षकों की अभिवृत्ति तथा विद्यालयी चुनौतियों का संयुक्त अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि अधिकांश शिक्षकों का दृष्टिकोण सकारात्मक था, किन्तु संसाधनों की कमी, बड़ी कक्षाएँ तथा विशेष शिक्षकों का अभाव समावेशन की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे।

18. शर्मा एवं चौहान (2024) ने समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कारकों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण, प्रशासनिक सहयोग, अभिभावकीय सहभागिता तथा पर्याप्त संसाधन समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। शोध ने बहुआयामी सहयोगात्मक मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया।
19. गुप्ता एवं पाण्डेय (2024) ने माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की चुनौतियों का अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि शिक्षकों को समय प्रबंधन, पाठ्यक्रम अनुकूलन तथा व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएँ तैयार करने में कठिनाई होती है। अध्ययन ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित किया।
20. मिश्रा एवं यादव (2025) ने समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं चुनौतियों का व्यापक अध्ययन किया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति समावेशी शिक्षा के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किन्तु संसाधनों की कमी, प्रशासनिक समर्थन का अभाव तथा प्रशिक्षण की सीमाएँ प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं। अध्ययन ने समावेशी शिक्षा के लिए समग्र एवं बहुस्तरीय रणनीति अपनाने की अनुशंसा की।

### **3. अध्ययन के उद्देश्य**

1. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना।
3. समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

### **4. परिकल्पनाएँ**

1. शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है।
2. समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

### **5. शोध पद्धति**

एक वर्णनात्मक सर्वेक्षणात्मक शोध है। इस शोध पद्धति का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति वर्तमान अभिवृत्तियों, विचारों, अनुभवों तथा उनके समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। वर्णनात्मक सर्वेक्षणात्मक शोध सामाजिक एवं शैक्षिक अनुसंधानों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली विधि है, जिसके माध्यम से किसी

समूह की विद्यमान परिस्थितियों, धारणाओं तथा व्यवहारों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का क्षेत्र विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तक सीमित रखा गया। शोध के लिए कुल 120 शिक्षकों का चयन किया गया, जो अध्ययन के लिए प्रतिनिधिक नमूना प्रदान करते हैं। इन शिक्षकों का चयन सरल यादृच्छिक निदर्शन विधि) के माध्यम से किया गया, जिससे समग्र के प्रत्येक सदस्य को चयनित होने का समान अवसर प्राप्त हो सके तथा चयन पक्षपात की संभावना न्यूनतम रहे। अध्ययन में प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्रश्नावली का निर्माण अध्ययन के उद्देश्यों, समावेशी शिक्षा से संबंधित साहित्य तथा विशेषज्ञों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए किया गया। प्रश्नावली में शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण, समावेशी शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े प्रश्न सम्मिलित किए गए। प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पूर्व उसकी वैधता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया गया। संकलित आँकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग किया गया। प्रतिशत विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न प्रतिक्रियाओं का वर्गीकरण एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिससे शिक्षकों की अभिवृत्तियों एवं चुनौतियों की स्पष्ट व्याख्या संभव हो सकी। इस प्रकार अपनाई गई शोध पद्धति अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा विश्वसनीय निष्कर्षों के निर्माण के लिए उपयुक्त एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है।

## 6. आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

### सारणी 1: समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति

अभिवृत्ति स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
उच्च	72	60
मध्यम	36	30
निम्न	12	10
कुल	120	100

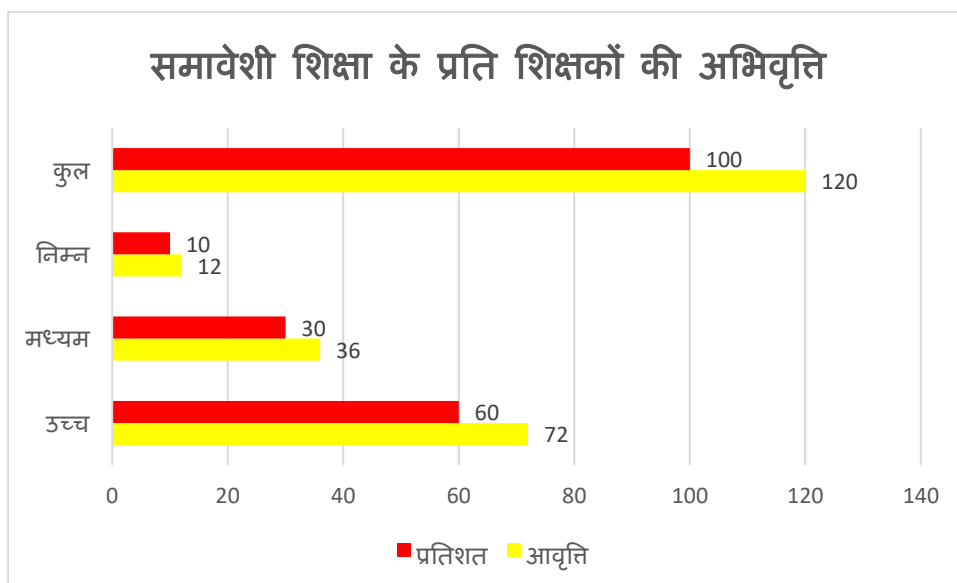
#### व्याख्या

प्रस्तुत सारणी के सांख्यिकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 120 शिक्षकों में से 72 शिक्षक (60%) समावेशी शिक्षा के प्रति उच्च स्तर की सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, जबकि 36 शिक्षक (30%) मध्यम स्तर की अभिवृत्ति प्रदर्शित करते हैं तथा केवल 12 शिक्षक (10%) निम्न स्तर की अभिवृत्ति रखते हैं। यह

वितरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अध्ययन समूह के अधिकांश शिक्षक समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसके उद्देश्यों तथा उसके शैक्षिक महत्त्व के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं।

सांख्यिकीय दृष्टि से यदि उच्च एवं मध्यम अभिवृत्ति वाले शिक्षकों को संयुक्त रूप से देखा जाए, तो उनकी संख्या 108 (90%) है, जो यह इंगित करती है कि समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मकता का स्तर अत्यधिक सुदृढ़ है। वहीं निम्न अभिवृत्ति वाले शिक्षकों का प्रतिशत मात्र 10 प्रतिशत है, जो अपेक्षाकृत नगण्य माना जा सकता है। यह प्रवृत्ति इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों, समान अवसरों तथा शिक्षा में सामाजिक न्याय की अवधारणा के प्रति व्यापक स्वीकृति विद्यमान है।

शैक्षिक दृष्टिकोण से यह परिणाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी समावेशी कार्यक्रम की सफलता शिक्षकों की अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें सामान्य कक्षा में समायोजित करने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त, यह निष्कर्ष भी निकलता है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की नीतियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं जागरूकता अभियानों ने शिक्षकों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है। अतः कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों की अभिवृत्ति एक सशक्त आधार प्रदान करती है तथा यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समावेशिता के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देती है।



**सारणी 2: समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ**

चुनौती	आवृत्ति	प्रतिशत
प्रशिक्षण का अभाव	38	31.67
संसाधनों की कमी	30	25.00
बड़ी कक्षाएँ	24	20.00
प्रशासनिक सहयोग का अभाव	18	15.00
अभिभावकों की जागरूकता का अभाव	10	8.33
कुल	120	100

### व्याख्या

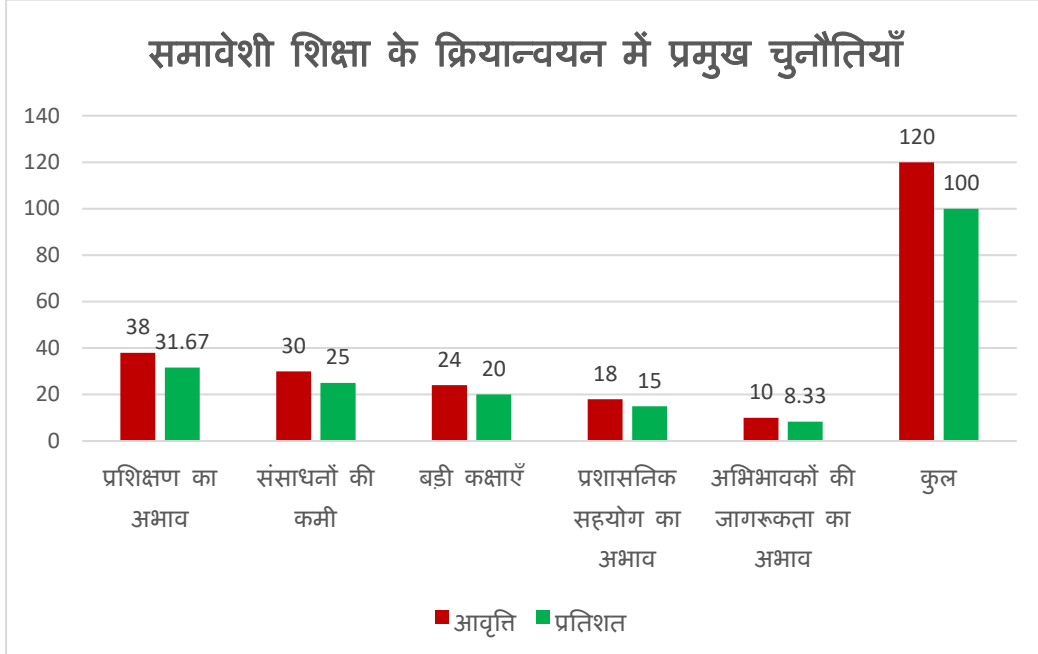
सारणी 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में सम्मिलित 120 शिक्षकों में से 38 शिक्षकों (31.67%) ने प्रशिक्षण के अभाव को सर्वाधिक गंभीर चुनौती माना है। यह प्रतिशत अन्य सभी चुनौतियों की तुलना में अधिक है, जो यह दर्शाता है कि समावेशी शिक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षकों में आवश्यक दक्षताओं एवं विशेष शिक्षण कौशलों का अभाव विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त 30 शिक्षकों (25.00%) ने संसाधनों की कमी को प्रमुख समस्या के रूप में चिह्नित किया। संसाधनों की कमी में सहायक शिक्षण सामग्री, विशेष उपकरण, अनुकूल अधिगम वातावरण तथा तकनीकी सुविधाओं का अभाव सम्मिलित है। वहीं 24 शिक्षकों (20.00%) ने बड़ी कक्षाओं को समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बताया। बड़ी कक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना कठिन हो जाता है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो प्रशिक्षण के अभाव एवं संसाधनों की कमी को मिलाकर कुल 56.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन्हें प्रमुख बाधा माना है। यह अनुपात आधे से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो इन दोनों कारकों की गंभीरता को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त 15 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशासनिक सहयोग के अभाव तथा 8.33 प्रतिशत शिक्षकों ने अभिभावकों की जागरूकता की कमी को चुनौती के रूप में इंगित किया।

इन परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन, पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएँ,

प्रशासनिक सहयोग तथा अभिभावकीय सहभागिता भी अनिवार्य है। अतः सरकार एवं शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षकों के क्षमता-विकास कार्यक्रमों तथा संसाधन सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।



**सारणी 3: समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक सुधार**

सुधारात्मक उपाय	आवृत्ति	प्रतिशत
नियमित प्रशिक्षण	45	37.50
संसाधनों की उपलब्धता	32	26.67
विशेषज्ञ सहयोग	23	19.16
प्रशासनिक समर्थन	20	16.67
कुल	120	100

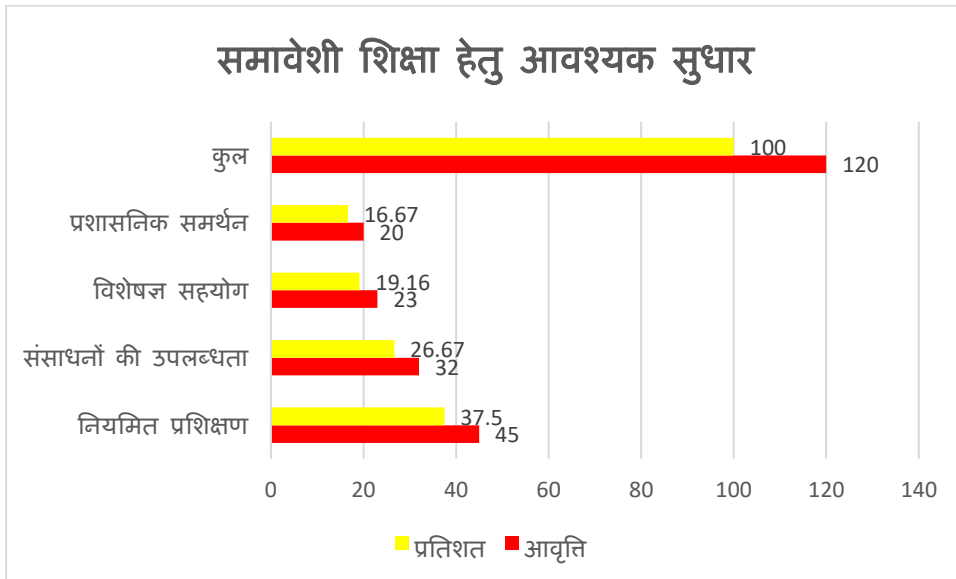
### व्याख्या

सारणी 3 के आंकड़ों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि शिक्षकों ने समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। कुल 120 शिक्षकों में से 45 शिक्षकों (37.50%) ने नियमित प्रशिक्षण को सर्वाधिक आवश्यक सुधारात्मक उपाय माना है। यह सर्वाधिक प्रतिशत दर्शाता है कि शिक्षक स्वयं को समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

इसी प्रकार 32 शिक्षकों (26.67%) ने संसाधनों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण माना। यह परिणाम इंगित करता है कि समावेशी शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु केवल प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि

सहायक अधिगम सामग्री, विशेष शिक्षण उपकरण, तकनीकी संसाधन एवं अनुकूल भौतिक वातावरण भी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त 23 शिक्षकों (19.16%) ने विशेषज्ञ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इसका अर्थ है कि विशेष शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं तथा पुनर्वास विशेषज्ञों का सहयोग सामान्य शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

सांख्यिकीय दृष्टि से यदि नियमित प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता को संयुक्त रूप से देखा जाए तो 64.17 प्रतिशत शिक्षकों ने इन्हें प्राथमिक सुधारात्मक आवश्यकता माना है। यह बहुमत इस तथ्य को रेखांकित करता है कि समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्षमता निर्माण और संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं 16.67 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशासनिक समर्थन को आवश्यक बताया, जो यह संकेत करता है कि विद्यालय प्रशासन की सक्रिय भूमिका भी समावेशी वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण है।



यह निष्कर्ष निकलता है कि समावेशी शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन बहुआयामी एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण की मांग करता है। नियमित प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा सुदृढ़ प्रशासनिक सहयोग के समन्वित प्रयासों से ही समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ये निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों तथा विद्यालय प्रबंधकों के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

## 7. विचार-विमर्श

1. प्रस्तुत सारणी के सांख्यिकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 120 शिक्षकों में से 72 शिक्षक (60%) समावेशी शिक्षा के प्रति उच्च स्तर की सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, जबकि 36 शिक्षक (30%) मध्यम स्तर की अभिवृत्ति प्रदर्शित करते हैं तथा केवल 12

शिक्षक (10%) निम्न स्तर की अभिवृत्ति रखते हैं। यह वितरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अध्ययन समूह के अधिकांश शिक्षक समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसके उद्देश्यों तथा उसके शैक्षिक महत्त्व के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं।

2. सांख्यिकीय दृष्टि से यदि उच्च एवं मध्यम अभिवृत्ति वाले शिक्षकों को संयुक्त रूप से देखा जाए, तो उनकी संख्या 108 (90%) है, जो यह इंगित करती है कि समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मकता का स्तर अत्यधिक सुदृढ़ है। वहीं निम्न अभिवृत्ति वाले शिक्षकों का प्रतिशत मात्र 10 प्रतिशत है, जो अपेक्षाकृत नगण्य माना जा सकता है। यह प्रवृत्ति इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों, समान अवसरों तथा शिक्षा में सामाजिक न्याय की अवधारणा के प्रति व्यापक स्वीकृति विद्यमान है।
3. शैक्षिक दृष्टिकोण से यह परिणाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी समावेशी कार्यक्रम की सफलता शिक्षकों की अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें सामान्य कक्षा में समायोजित करने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त, यह निष्कर्ष भी निकलता है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की नीतियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं जागरूकता अभियानों ने शिक्षकों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है। अतः कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों की अभिवृत्ति एक सशक्त आधार प्रदान करती है तथा यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समावेशिता के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देती है।
4. सारणी 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में सम्मिलित 120 शिक्षकों में से 38 शिक्षकों (31.67%) ने प्रशिक्षण के अभाव को सर्वाधिक गंभीर चुनौती माना है। यह प्रतिशत अन्य सभी चुनौतियों की तुलना में अधिक है, जो यह दर्शाता है कि समावेशी शिक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षकों में आवश्यक दक्षताओं एवं विशेष शिक्षण कौशलों का अभाव विद्यमान है।
5. इसके अतिरिक्त 30 शिक्षकों (25.00%) ने संसाधनों की कमी को प्रमुख समस्या के रूप में चिह्नित किया। संसाधनों की कमी में सहायक शिक्षण सामग्री, विशेष उपकरण, अनुकूल अधिगम वातावरण तथा तकनीकी सुविधाओं का अभाव सम्मिलित है। वहीं 24 शिक्षकों (20.00%) ने बड़ी कक्षाओं को समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बताया। बड़ी कक्षाओं में प्रत्येक

विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना कठिन हो जाता है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

6. सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो प्रशिक्षण के अभाव एवं संसाधनों की कमी को मिलाकर कुल 56.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन्हें प्रमुख बाधा माना है। यह अनुपात आधे से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो इन दोनों कारकों की गंभीरता को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त 15 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशासनिक सहयोग के अभाव तथा 8.33 प्रतिशत शिक्षकों ने अभिभावकों की जागरूकता की कमी को चुनौती के रूप में इंगित किया।
7. इन परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन, पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएँ, प्रशासनिक सहयोग तथा अभिभावकीय सहभागिता भी अनिवार्य है। अतः सरकार एवं शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षकों के क्षमता-विकास कार्यक्रमों तथा संसाधन सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
8. सारणी 3 के आंकड़ों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि शिक्षकों ने समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। कुल 120 शिक्षकों में से 45 शिक्षकों (37.50%) ने नियमित प्रशिक्षण को सर्वाधिक आवश्यक सुधारात्मक उपाय माना है। यह सर्वाधिक प्रतिशत दर्शाता है कि शिक्षक स्वयं को समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता अनुभव करते हैं।
9. इसी प्रकार 32 शिक्षकों (26.67%) ने संसाधनों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण माना। यह परिणाम इंगित करता है कि समावेशी शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु केवल प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सहायक अधिगम सामग्री, विशेष शिक्षण उपकरण, तकनीकी संसाधन एवं अनुकूल भौतिक वातावरण भी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त 23 शिक्षकों (19.16%) ने विशेषज्ञ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इसका अर्थ है कि विशेष शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं तथा पुनर्वास विशेषज्ञों का सहयोग सामान्य शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
10. सांख्यिकीय दृष्टि से यदि नियमित प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता को संयुक्त रूप से देखा जाए तो 64.17 प्रतिशत शिक्षकों ने इन्हें प्राथमिक सुधारात्मक आवश्यकता माना है। यह बहुमत इस तथ्य को रेखांकित करता है कि समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्षमता निर्माण

और संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं 16.67 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशासनिक समर्थन को आवश्यक बताया, जो यह संकेत करता है कि विद्यालय प्रशासन की सक्रिय भूमिका भी समावेशी वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण है।

11. समावेशी शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन बहुआयामी एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण की मांग करता है। नियमित प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा सुदृढ़ प्रशासनिक सहयोग के समन्वित प्रयासों से ही समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ये निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों तथा विद्यालय प्रबंधकों के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

## 8. परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना था। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए—

### 1. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक पाई गई

अध्ययन में सम्मिलित 120 शिक्षकों में से 72 (60%) शिक्षकों की अभिवृत्ति उच्च स्तर की, 36 (30%) शिक्षकों की अभिवृत्ति मध्यम स्तर की तथा केवल 12 (10%) शिक्षकों की अभिवृत्ति निम्न स्तर की पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश शिक्षक समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्यों एवं उपयोगिता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यह परिणाम इंगित करता है कि शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं में सम्मिलित करने के पक्षधर हैं तथा शिक्षा में समान अवसरों की अवधारणा को स्वीकार करते हैं।

### 2. प्रशिक्षण का अभाव सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा

समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में 38 (31.67%) शिक्षकों ने प्रशिक्षण के अभाव को प्रमुख चुनौती माना। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं दक्षताओं का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। यह स्थिति समावेशी शिक्षा के प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न करती है।

### 3. संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है

अध्ययन में 30 (25%) शिक्षकों ने संसाधनों की कमी को प्रमुख चुनौती बताया। इससे ज्ञात होता है कि विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री, विशेष उपकरण, तकनीकी सुविधाएँ तथा समावेशी अधिगम वातावरण का अभाव है, जो समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

#### **4. बड़ी कक्षाएँ समावेशी शिक्षा के लिए बाधक हैं**

24 (20%) शिक्षकों ने अत्यधिक छात्र संख्या वाली कक्षाओं को समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन में बाधक माना। बड़ी कक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान देना कठिन हो जाता है, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में।

#### **5. प्रशासनिक एवं अभिभावकीय सहयोग अपेक्षाकृत कम पाया गया**

18 (15%) शिक्षकों ने प्रशासनिक सहयोग के अभाव तथा 10 (8.33%) शिक्षकों ने अभिभावकों की जागरूकता के अभाव को प्रमुख चुनौती के रूप में इंगित किया। इससे स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है।

#### **6. नियमित प्रशिक्षण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय माना गया**

45 (37.50%) शिक्षकों ने नियमित प्रशिक्षण को समावेशी शिक्षा के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय माना। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक स्वयं अपनी व्यावसायिक दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

#### **7. संसाधनों की उपलब्धता एवं विशेषज्ञ सहयोग की आवश्यकता**

32 (26.67%) शिक्षकों ने संसाधनों की उपलब्धता तथा 23 (19.16%) शिक्षकों ने विशेषज्ञ सहयोग को आवश्यक सुधारात्मक उपाय बताया। इससे स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए बहु-विषयक सहयोग, आधुनिक संसाधन तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन अनिवार्य हैं।

#### **8. समावेशी शिक्षा की सफलता बहुआयामी प्रयासों पर निर्भर है**

अध्ययन के समग्र परिणाम यह संकेत देते हैं कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक होने के बावजूद प्रशिक्षण, संसाधन, विशेषज्ञ सहायता एवं प्रशासनिक समर्थन जैसी चुनौतियाँ इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। अतः समावेशी शिक्षा की सफलता हेतु शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन विकास, संस्थागत सहयोग तथा समुदाय की सहभागिता को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

#### **संक्षिप्त परिणाम**

1. 60% शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति उच्च अभिवृत्ति पाई गई।

2. 31.67% शिक्षकों ने प्रशिक्षण के अभाव को प्रमुख चुनौती माना।
3. 25% शिक्षकों ने संसाधनों की कमी को महत्वपूर्ण समस्या बताया।
4. 20% शिक्षकों ने बड़ी कक्षाओं को बाधक माना।
5. 15% शिक्षकों ने प्रशासनिक सहयोग के अभाव को चुनौती माना।
6. 37.50% शिक्षकों ने नियमित प्रशिक्षण को सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय माना।
7. 26.67% शिक्षकों ने संसाधनों की उपलब्धता पर बल दिया।
8. समावेशी शिक्षा की सफलता प्रशिक्षण, संसाधनों, विशेषज्ञ सहयोग एवं प्रशासनिक समर्थन पर निर्भर पाई गई।

### 9. निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सामान्यतः सकारात्मक है। अधिकांश शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा में सम्मिलित करने के पक्षधर हैं। तथापि प्रशिक्षण की कमी, अधोसंरचनात्मक सीमाएँ, संसाधनों का अभाव तथा प्रशासनिक समर्थन की कमी समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख अवरोध हैं। अतः सरकार, विद्यालय प्रशासन तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना चाहिए।

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना तथा समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना था। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों एवं उनके सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं—

#### उद्देश्य 1: समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश शिक्षकों की अभिवृत्ति समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक एवं अनुकूल है। कुल 60 प्रतिशत शिक्षकों की अभिवृत्ति उच्च स्तर की तथा 30 प्रतिशत शिक्षकों की अभिवृत्ति मध्यम स्तर की पाई गई। केवल 10 प्रतिशत शिक्षकों की अभिवृत्ति निम्न स्तर की रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसके उद्देश्यों तथा समान शैक्षिक अवसरों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। वे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर हैं तथा शिक्षा में समानता, सामाजिक न्याय एवं सहभागिता को महत्वपूर्ण मानते हैं। अतः यह

निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण सामान्यतः सकारात्मक एवं प्रगतिशील है, जो इसके सफल क्रियान्वयन के लिए एक अनुकूल आधार प्रदान करता है।

### **उद्देश्य 2: समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना**

अध्ययन के दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में शिक्षकों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का विश्लेषण किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षण का अभाव सबसे प्रमुख चुनौती है, जिसे 31.67 प्रतिशत शिक्षकों ने स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त संसाधनों की कमी (25%), बड़ी कक्षाएँ (20%), प्रशासनिक सहयोग का अभाव (15%) तथा अभिभावकों की जागरूकता का अभाव (8.33%) भी महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में सामने आए। इससे स्पष्ट होता है कि सकारात्मक अभिवृत्ति होने के बावजूद शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, अधोसंरचना एवं सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतिगत प्रावधानों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके लिए पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक, सहयोगात्मक वातावरण तथा संस्थागत समर्थन भी आवश्यक है

### **उद्देश्य 3: समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायों का अध्ययन करना**

अध्ययन के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों का भी विश्लेषण किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि नियमित प्रशिक्षण (37.50%) को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय माना गया। इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता (26.67%), विशेषज्ञ सहयोग (19.16%) तथा प्रशासनिक समर्थन (16.67%) को भी आवश्यक बताया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बहुआयामी एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं का विकास, विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा विशेषज्ञों का सहयोग समावेशी वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अध्ययन यह सिद्ध करता है कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक एवं आशावादी है, जो इसकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। तथापि, प्रशिक्षण की कमी, संसाधनों का अभाव, बड़ी कक्षाएँ तथा अपर्याप्त प्रशासनिक सहयोग जैसी व्यावहारिक चुनौतियाँ इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि यदि शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराया जाए तो समावेशी शिक्षा को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सफल बनाया जा सकता है। अतः शिक्षा व्यवस्था में समावेशिता को सुदृढ़ करने

के लिए नीति-निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों तथा अभिभावकों के बीच समन्वित एवं सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

## 10. सुझाव

1. शिक्षकों के लिए नियमित समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
2. विद्यालयों में विशेष शिक्षण-सामग्री एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।
3. विशेष शिक्षकों एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाए।
4. अभिभावकों को समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जाए।
5. विद्यालय प्रशासन द्वारा निरंतर सहयोग एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए।

## संदर्भ सूची

1. अरोरा, ए., एवं सिंह, आर. (2019). समावेशी शिक्षा में अवसर एवं चुनौतियाँ: भारतीय विद्यालयों का एक अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, 8(2), 45–58।
2. बेस्ट, जे. डब्ल्यू., एवं कान, जे. वी. (2018). शिक्षा में अनुसंधान (14वाँ संस्करण)। पियर्सन एजुकेशन।
3. भट्टाचार्य, एस. (2020). समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति: भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन। शैक्षिक अध्ययन पत्रिका, 15(1), 23–35।
4. बून, आर. टी., एवं शर्मा, यू. (2015). समावेशी शिक्षा एवं शिक्षक तैयारी: साहित्य का पुनरावलोकन। अंतर्राष्ट्रीय समावेशी शिक्षा पत्रिका, 19(4), 421–438।
5. देसाई, आई. (2021). माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ। भारतीय शैक्षिक प्रशासन पत्रिका, 13(2), 67–81।
6. फ्लोरियन, एल. (2014). विशिष्ट शिक्षा की सेज हस्तपुस्तिका (द्वितीय संस्करण)। सेज प्रकाशन।
7. गुप्ता, पी., एवं वर्मा, एस. (2018). शिक्षकों की धारणा एवं समावेशी कक्षा व्यवहार। एजुकेशनल क्वेस्ट, 9(3), 189–197।
8. कौर, ए., एवं अरोड़ा, एस. (2022). समावेशी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति। विकलांगता अध्ययन पत्रिका, 10(1), 55–69।
9. मिश्रा, एस., एवं पाण्डेय, एम. (2021). भारत में समावेशी शिक्षा: नीति एवं व्यवहार। यूनिवर्सिटी न्यूज़, 59(12), 15–21।

10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। (2006). समावेशी शिक्षा: शिक्षकों हेतु मार्गदर्शिका। नई दिल्ली: एनसीईआरटी।
11. पाण्डेय, आर. एस. (2017). शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ। आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
12. राव, वी., एवं रेड्डी, के. (2019). भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की बाधाएँ। एशियाई शिक्षा एवं सामाजिक अध्ययन पत्रिका, 5(2), 1–10।
13. शर्मा, यू., फोरेलिन, सी., एवं मॉर्गन, एम. (2013). प्रशिक्षण का समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति पर प्रभाव। शिक्षण एवं शिक्षक शिक्षा पत्रिका, 35, 13–21।
14. शर्मा, यू., एवं नॉरलिन, सी. (2016). समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अंतर्राष्ट्रीय समावेशी शिक्षा पत्रिका, 20(6), 619–635।
15. सिंह, आर., एवं यादव, पी. (2020). शासकीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों की तत्परता। भारतीय शैक्षिक समीक्षा, 58(1), 92–108।
16. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। (1994). विशेष आवश्यकता शिक्षा पर सलामांका घोषणा एवं कार्य रूपरेखा। पेरिस: यूनेस्को।
17. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। (2020). वैश्विक शिक्षा निगरानी प्रतिवेदन 2020: समावेशन और शिक्षा – सबके लिए शिक्षा। पेरिस: यूनेस्को।
18. वर्मा, एस., एवं गुप्ता, डी. (2021). समावेशी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताएँ। शैक्षिक नवाचार पत्रिका, 7(2), 34–48।
19. विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2011). विकलांगता पर विश्व प्रतिवेदन। जेनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।
20. यादव, ए., एवं मिश्रा, आर. (2022). समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियाँ। शिक्षा में अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, 11(3), 112–126।